



2026:AHC:68075

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या-- 4476 वर्ष 2026

ब्रह्मजीत सिंह और 5 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आनंद कुमार, नंदिनी, रेणु चौकल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 52

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

-

I- परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें प्रतिपक्षी संख्या-2 को 12.08.2025 के आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है, जिसे याचिकाकर्ता संख्या-1 से 6 द्वारा इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर भेजा गया है।

II- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझे।

III- आवेदक को याचिका की लागत प्रदान करना।

शुरुआत में, स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत याचिका अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जो सुनवाई योग्य नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने ए.पी.एस.आर.टी.सी. और अन्य बनाम जी. श्रीनिवास रेड्डी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और अन्य ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 1465 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि प्रतिनिधित्व तय करने के लिए प्रार्थना के साथ एक रिट सुनवाई योग्य नहीं है यदि अभ्यावेदन दाखिल करने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है: -

19. ऐसे कई उदाहरण भी हैं जहां "लचीले" अधिकारियों की मिलीभगत से बेईमान याचिकाकर्ताओं ने अदालत द्वारा जारी "विचार करने" के निर्देश का दुरुपयोग किया है। हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। एक दावा, जो बासी, समय-वर्जित या अस्थिर है, एक प्रतिनिधित्व के रूप में सामने रखा जाता है। इस आधार पर कि प्राधिकरण ने उचित समय के भीतर प्रतिनिधित्व का निपटान नहीं किया है, प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति प्राधिकरण को अभ्यावेदन पर "विचार" करने और उसका निपटान करने का निर्देश देने के लिए एक अहानिकर प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। जब अदालत "विचार" करने के निर्देश के साथ याचिका का निस्तारण करती है, तो प्राधिकरण अदालत के आदेश के तहत राहत प्रदान करता है, उसे राहत देने पर "विचार" करने का निर्देश देता है। ऐसे उदाहरण भी नहीं हैं जहां रिट कार्यवाही और न्यायिक समीक्षा की बारीकियों से संबंधित प्रक्रिया और अभ्यास से अपरिचित अधिकारियों ने "विचार करने के लिए" आदेश की व्याख्या या समझ ली है, जो अभ्यावेदन में मांगी गई राहत के अनुदान को निर्देशित करने के रूप में है और परिणामस्वरूप राहत प्रदान कर रही है जो अन्यथा प्रदान नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार, "विचार" करने के आदेशों के अनुसरण में अयोग्य राहत देने वाले अधिकारियों की कार्रवाई, अज्ञानता के कारण हो सकती है, या वास्तविक विश्वास के कारण हो सकती है कि उन्हें दावे पर "विचार" करने के लिए अदालत के निर्देश के मद्देनजर राहत देनी चाहिए, या प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति और इसे तय करने वाले प्राधिकरण के बीच मिलीभगत/मिलीभगत के कारण। नियमित सेवा में नियमितीकरण/अवशोषण की मांग करने वाले



दैनिक मजदूरों का प्रतिनिधित्व मामलों की एक प्रजाति है, जहां "विचार करने" के आदेशों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है।

दया शंकर पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2001 (1) एडब्लूसी 671 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया जा सकता है। उक्त निर्णय का प्रस्तर-15 इस प्रकार है: -

"15. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति को अस्वीकार करने वाले डी.आई.ओ.एस. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने 14.11.2000 को शिक्षा उपनिदेशक के समक्ष 16.3.1999 को अपील/अभ्यावेदन दायर किया है और उपरोक्त अपील/अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए एक निर्देश जारी किया जाए। तर्क दो कारणों से किसी भी योग्यता से रहित है। पहला, दूसरा आदेश जिसके तहत अल्पकालिक रिक्तियों पर नियुक्तियां की जाती हैं, शिक्षा उपनिदेशक या शिक्षा निदेशक को किसी भी अपील/प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं करता है। अपील का प्रावधान केवल प्रथम क्रम में था जहां मूल रिक्तियों के खिलाफ नियुक्तियों की गई थीं। चूंकि राज्य सरकार ने अल्पकालिक नियुक्तियों के खिलाफ शैक्षिक अधिकारियों को कोई अपील या प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया था, इसलिए याचिकाकर्ता की अपील/अभ्यावेदन कानून के किसी भी प्रावधान के तहत नहीं किए गए थे, इसलिए, इसे तय करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि पहले और दूसरे आदेश को 25.1.1999 से हटा दिया गया है और वे अब अस्तित्व में नहीं हैं, याचिकाकर्ता द्वारा पहले या दूसरे आदेश के तहत कोई अपील/प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह माना गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति दोषपूर्ण थी क्योंकि यह कठिनाइयों को हटाने के आदेश के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी, याचिकाकर्ता की अपील/प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए शैक्षिक अधिकारियों को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।



उपरोक्त आपत्तियों पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने नई सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की प्रार्थना की। तदनुसार, इस याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया जाता है।

मार्च 31, 2026

जितेंद्र/-

(न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान)

Translated Version. Not for Legal Use.